गलत इलाज से पहुंचे मौत के करीब, अब मंगा रहे विदेशों से दवा

लगातार बढ़ रही है देश में टीबी के गंभीर मरीजों की संख्या

प्रदीप सुरीन | नई दिल्ली

22 साल की शारदा (बदला हुआ नाम) एक्सएक्सडीआर-टीबी (टीबी का सबसे घातक रूप) से संक्रमित है। 10वीं की परीक्षा के बाद से 2013 में पता चला कि उन्हें टीबी है। पहले प्राइवेट फिर सरकारी अस्पताल में इलाज कराया। पर मामला और बिगड़ गया। इसी दौरान माता-पिता का निधन हो गया और तंगी में इलाज में कोताही भी हो गई। पिछले साल जनवरी में विभिन्न जांचों के बाद पता चला कि उन्हें एक्सएक्सडीआर-टीबी हो गया है। हाल में उन्हें अंतरराष्ट्रीय संगठन डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर (एमएसएफ) की मदद से 'डेलामनिड' दवा उपलब्ध कराई जा रही है। शारदा बताती हैं कि सरकारी डाक्टर बोल चुके थे कि अब मेरा बचना मुश्किल है। लेकिन सही समय पर मेरे निजी निवेदन पर जापानी दवा कंपनी ओटसूका ने मुफ्त 'डेलामनिड' दवा उपलब्ध कराई है। नवंबर में हुए बलगम और एक्स-रे जांच में सुधार हुआ है। वजन भी बढ़ रहा है।

अंधेरी के स्लम में रहने वाली अक्षता (बदला हुआ नाम) का मामला भी कुछ ऐसा ही है। 2013 में नौवीं में पढ़ने वाली अक्षता का वजन कम होने और पेट में दर्द के बाद जांच कराई गई। एमडीआर- टीबी (मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट-टीबी) होने पर पहले निजी क्लीनिक फिर सरकारी चिकित्सालय में इलाज हुआ। डाक्टरों ने अपने-अपने तरीके से इलाज किया। 2014 में जांच में पता चला कि उन्हें पहले से भी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा एक्सडीआर-टीबी हो गया है। अक्षता कहती हैं कि डाक्टरों के मनमाने इलाज करने के तरीके ने ही उन्हें मौत के करीब पहुंचा दिया था। इसके बाद कुछ बड़े डाक्टरों की मदद से उन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन दवा कंपनी की नई दवा 'बेडाक्वीलीन' उपलब्ध कराने का निवेदन किया। कंपनी ने उन्हें मुफ्त दवाएं भारत में उपलब्ध कराई। अक्षता का वजन बढ़ने लगा है। दिसंबर में बलगम जांच में उन्हें अब एक्सडीआर-टीबी मुक्त पाया गया।

लेकिन शारदा और अक्षता कुछ खुशनसीब मरीज हैं। देश में एक्सडीआर-टीबी और एक्सएक्सडीआर- टीबी के तीन हजार से ज्यादा मरीज हैं। इन पर भारत में मौजूदा सभी टीबी की दवाएं निष्क्रिय हो गई हैं या फिर होने के कगार पर हैं। दवाओं के निष्क्रिय होने की मुख्य वजह इलाज के लिए तैयार राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करना है। निजी अस्पतालों और डाक्टरों का टीबी मरीजों की जानकारी छुपाना भी इसका एक कारण बनकर उभरी है।

मेडिकल पत्रिका "लैंसेट" का दावा

भारत में 35 लाख टीबी मरीज, 14 लाख आ रहे सरकारी अस्पताल।

डब्ल्यूएचओः ग्लोबल टीबी रिपोर्ट- 2016

- भारत में हर साल 28 लाख लोग होते हैं टीबी संक्रमित। दुनिया के मरीजों में 27 फीसदी भारतीय।
- भारत में लगभग 3,048 मरीज एक्सडीआर-टीबी से संक्रमित।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय

जल्द लगभग 600 और एक्सडीआर-टीबी मरीजों को भी बेडाक्वीलीन मिलने लगेगी।

निजी अस्पतालों की सुस्ती भारी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के डीडीजी डॉ. सुनिल खरपडे का कहना है कि भारत सरकार ने 2012 में ही टीबी को अधिसूचित बीमारी घोषित कर दिया है। नए नियम के तहत सभी निजी अस्पतालों को नए और मौजूदा टीबी मरीजों की जानकारी स्थानीय प्रशासन के साथ साझा करना अनिवार्य है। बावजूद ज्यादातर निजी अस्पताल और नर्सिंग होम टीबी मरीजों की जानकारी सरकार को नहीं बताते। केंद्र सरकार ने हाल ही में तीन निजी अस्पतालों के साथ पायलट प्रोजेक्ट के तहत मुफ्त दवाएं और डाक्टरों को प्रोत्साहन राशि देने की योजना को चलाई है। इसके अच्छे नतीजे सामने आए हैं।

सरकारी-निजी अस्पताल में संवाद कम

भारत में अभी टीबी नियंत्रण के लिए निजी और सरकारी अस्पतालों में एक तय मानदंड से इलाज नहीं हो रहा है। इसलिए देश में टीबी दवाओं के निष्क्रिय होने के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। नए ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में निजी अस्पतालों से कुल 1.84 लाख मरीजों की जानकारी साझा हुई है। इनमें से भी 20 फीसदी (लगभग 30 हजार मरीजों की जानकारी तीन ऐसे निजी अस्पतालों से साझा हुई है, जहां केंद्र सरकार एक पायलट प्रोजेक्ट चला रही है)।

आखिर क्यों केंद्र है चुप?

एक्वीटिस सॉल्टिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. बॉबी जॉन का सवाल है कि आखिर क्यों केंद्र सरकार टीबी को अधिसूचित करने के बावजूद निजी अस्पतालों पर लगाम नहीं कस पाई है? जैसे केंद्र सरकार इनकम टैक्स के लिए आम लोगों से अपील करती है। वैसे ही कुछ प्रो गाम चलाए। वरना निजी अस्पताल टीबी के नए मामलों को सरकार के साथ साझा नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनकी आय को सरकार के साथ साझा करने का माध्यम बन सकते हैं। डॉ. बॉबी का सुझाव है कि मरीजों को मोबाइल फोन के जरिए मिस कॉल से टीबी रिपोर्टिंग की सेवा मिलनी चाहिए।